(c) Hindustan Lever with assets well over Rs. 20 crores, is a large house under the Licensing Policy and under the MRTP Act. A large house can be allowed to enter only in core sector or export-oriented activities irrespective of the proportion of foreign equity.

Export Obligation of FERA Companies

5295. SHRI BHAUSAHEB THORAT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) is it true that an export obligation of 10 per cent is imposed on companies allowed to retain a foreign equity of 51 per cent; and

(b) how much foreign exchange has the country lost, as a result of persuading companies to reduce their foreign equity to 40 per cent, thereby having no export obligations?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): (a) Yes, Sir. Companies which are eligible to retain 51 per cent non-resident equity under guidelines are also required to maintain an export obligation of at least 10 per cent of their turnover.

(b) The eligibility of a foreign company to retain higher foreign equity is decided taking into account the contribution which the company makes to the economy by way of production in the 'Industries listed in Appendix I' of the Industrial Licensing Policies of 1973, its exports and its activities involving sophisticated technology. If a company is not eligible to be allowed to retain 51 per cent non-resident equity on the basis of these criteria it cannot be allowed this facility merely on the ground that it would export 10 per cent. in future. It is not also feasible to isolate exports only for FERA purposes, nor quantify national export loss on this count, as different companies would have performed differently and there are companies with impressive export performance without any export obligation while there are companies with none-too-happy performance even with export obligation.

News-item Captioned "Super Bazar G. M. Relieved of Post"

5296. DR. A. U. AZMI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news item "Super Bazar G. M. relieved of Post" appearing at page 1 of the 'Indian Express' New Delhi dated the 11th March, 1981;

(b) if so, the facts of the case; and

(c) his reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES (SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY): (a) to (c). Yes, Sir. A request was received from the Managing Committee, Super Bazar, New Delhi to change the G.M. Accordingly, the G.M., Super Bazar has handed over charge of his post, as ordered by the Government, and proceeded on leave. Necessary steps are being taken to fill up the post.

देश में चल रहे न्यासों (ट्रस्टों) की संख्या

5297. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न नामों से चल रहे न्यासों की, राज्यवार, संख्या कितनी है और न्यासों में लगाई गई चल और अचल पूंजी कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यासों के सम्बन्ध में कोई आचार संहिता बनाई गई है, यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई संहिता बनाने का है, यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार के न्यासों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमिताओं और न्यास पूंजी का न्यासियों द्वारा अपने निजी व्यापार और धन्धे में लगाए जाने की जानकारी है; और क्या इसकी रोक थाम के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है; यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) देश में कर्य कर रहे न्यासों की संख्या बहुत अधिक है और सभी न्यासों के सम्बन्ध में, जिनमें से हो सकता है कुछ आयकर विभाग के रिकार्डों में हों ही नहीं, सूचना एकत्र करना कठिन होगा । प्रत्येक आयकर आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र में विद्यमान ऐसे न्यासों की संख्या से सम्बन्धित सूचना, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1980-81 के सम्बन्ध में छूट का दावा करते हैं, तथा कर निर्धारण वर्ष 1980-81 की संगत अवधि के लिए न्यासों में लगायी गयी चल और अचल पूंजी से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) धारा 11 के अन्तर्गत धर्मार्थ न्यासों को आयकर से छूट प्राप्त है बशर्ते कि वे ऐसी छूट के लिए अधिनियम में निर्धारित शर्तें पूरी करते हों । इस बारे की जानकारी नहीं है कि क्या राज्य सरकारों द्वारा न्यासों के सम्बन्ध में कोई आचार-संहिता तैयार की गई है ।

(ग) धारा 11 के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट न्यासों को उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होगी जब नियासियों द्वारा न्यास के धन का उपयोग उनके निजी व्यापार और कारोबार के लिये होता हो ।

गैर सरकारी वित्त कम्पनियां

5298. **श्री चन्द्र पाल शेखानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बहुत सी गैर-सरकारी वित्त कम्पनियां चल रही हैं जिनमें जनता की बहुत बड़ी धनराशि एक या दूसरे ढंग से लगी हुई है और यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें 1 जनवरी, 1981 को एक लाख रुपये से अधिक की प्राइवेट पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है कि इन कम्पनियों का जीवन बीमा निगम आदि जैसी सरकारी कम्पनियां, जो इसी उद्देश्य के लिए स्थापित की गई हैं, के कार्य संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): (क) और (ख) . सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Ban on Export of Iron ore.

5299. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) is it a fact that his Ministry has given orders to suspend/ban export of iron ore by M/s. Sociedade de Fomento Indus. Pvt. Ltd, and

(b) if so, why it is not being implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHED ALAM KHAN): (a) Yes, Sir. Instructions were issued to Iron Ore Adviser, Goa to suspend shipments of iron ore by M/s. Sociedade de Fomento indus. Pvt. Ltd. till they clear themselves with the income-tax authorities.

(b) M/s. Fomento filed a writ petition in the court of Judicial Commissioner, Goa, Daman and Diu against this order and obtained an ad-interim ex-parte stay order, and have been exporting iron ore in terms of this stay order. The next court hearing is likely to be fixed at the end of this month, when the question of vacation of the stay order will be taken up by the court.

Liability and Assets of Jaipur Udyog Limited

5300. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the total liability and assets of the Jaipur Udyog Ltd. and the extent amount invested in or loaned to it by various public financial institu-